POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 06 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! अप्रेल के ग्रामगदर में साफतौर पर कहा गया था कि 'अहसास यह हो रहा है कि इस बार मतदाता किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता की चाबी उसके हाथ में रख दें'..! यह मैं नहीं कह रहा था, देश के हालात इसे बयां कर रहे थे। जनता जनार्दन क्यों बदलाव चाहती हैं, इसका लेखा-जोखा भी पिछले दो अंकों में छपा है।

चुनाव परिणामों ने जनता के सपने को साकार कर दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दहाई के अंक से आगे नहीं बढ़ सके। क्षेत्रीय दल भी दहाई के अंक तक ही सिमट कर रह गए। शायद ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था।

दूसरी ओर मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिली अपूर्व सफलता ने एक नया इतिहास रच दिया। नतीजों से स्पष्ट है कि इस बार जनता ने जाति, क्षेत्र और मजहब की दीवारों को भी ढहा दिया और भाजपा व मोदी के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है।

खास बात यह है, चुनाव परिणामों ने देश की राजनीतिक दशा और दिशा को एक नया मोड़ दे दिया है। नई सरकार के लिए यह लाजमी हो गया है कि वह जनता के विश्वास पर खरी उतरे। इसके लिए योग्य और स्वच्छ छवि वाले सांसदों को ही मंत्री पद देना होगा।

सरकारी तंत्र की कार्यशैली में सुधार लाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि, इसी से सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जुड़ी है। महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी अनेक चुनौतियों से तभी निपटा जा सकेगा जब प्रशासन की सोच चुस्त और दुरुस्त होगी।

क्या कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम !

हर व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने और सूचना प्राप्त करने का हक है। इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना है।

- इस अधिनियम के तहत आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ्तर तक सभी सरकारी दफ्तरों से सूचना मांग सकते हैं। उनसे विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों में किए खर्च का आप लेखा-जोखा भी मांग सकते हैं।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ्तर में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है। आप इनसे इस बाबत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हर लोक सूचना अधिकारी आपको चाही गई जानकारी देने को बाध्य है।
- आप किसी भी सरकारी फाइल या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। उसकी प्रमाणित प्रति भी ले सकते हैं। आप किसी भी सरकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। काम में ली गई सामग्री के प्रमाणित नमूने भी ले सकते हैं। इस अधिकारी का यह दायित्व होगा की वह मांगी गई सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध कराए।
- सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ निर्धारित दस रुपए का शुल्क भी भुगतान करना होगा। आवेदक को विभाग का लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में चाही गई सूचना उपलब्ध कराएगा।
- यदि वह इस अवधि में सूचना नहीं देता है, तो आप राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा प्रथम अपील में जा सकते हैं।
- सूचना देने में असफल रहने पर लोक सूचना अधिकारी को कानूनी प्रवधानों के अनुसार 250 रुपए रोजाना के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपए तक का हर्जाना देना पड़ सकता है।

आंख खराब हुई, अस्पताल पर चार लाख का हर्जाना

उदयपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गांव कोकापुर निवासी सुभाष सेवक ने सागवाड़ा के पदमावती आई हॉस्पिटल के खिलाफ डूंगरपुर के उपभोक्ता मंच में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने उक्त हॉस्पिटल के डॉ. दिलीप शाह से मोतियाबिंद निकलवाने के लिए आंख का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उस आंख की रोशनी समाप्त हो गई।

उन्होंने मुंबई के कांदीवली स्थित आई हॉस्पिटल व दाहोद के अस्पताल में आंख की सर्जरी भी कराई मगर उस आंख की रोशनी नहीं लौटी। डूंगरपुर के उपभोक्ता मंच ने उनके परिवाद को खारिज कर दिया।

सुभाष सेवक ने इसकी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई। आयोग ने मामले की सुनवाई व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पदमावती आई हॉस्पिटल को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना। आयोग ने हॉस्पिटल को आदेश दिया कि वह सुभाष सेवक को चार लाख ग्यारह हजार रुपए का हर्जाना अदा करे।

लोक सभा में पहली बार

भाजपा को मिली प्रदेश की सभी 25 सीटें

'कट्स' द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश के विभिन्न जिलों में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से कराए गए सर्वे में प्रदेश के 76 फीसदी लोगों ने बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना जताई थी। प्रदेश के 67 फीसदी लोग नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना पसन्द करते थे। उनकी उम्मीदें इससे भी बढ़-चढ़ कर फलीभूत हुई हैं। प्रदेश में जहां सभी सीटों पर भाजपा को विजयश्री मिली, वहीं पूरे देश में एनडीए ने लोकसभा की 543 सीटों में से 336 पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अकेले दम पर ही भाजपा को 282 सीटें मिली है।

प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय मोदी जी और कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केन्द्र की मोदी सरकार में राजस्थान को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि मोदी जी राजस्थान की परिस्थितियों से भलि-भांति वाकिफ है और वे यहां की तकलीफों को समझते हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ने से प्रदेश को विकास के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि अब आचार संहिता समाप्त हो गई है सरकार पूरे जोश से विकास योजनाएं लागू करेगी।

हर ग्राम पंचायत में माध्यमिक स्कूल

राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में स्कूल एकीकरण योजना के तहत अब एक ही परिसर में चलने वाले एक से अधिक स्कूल एक हो जाएंगे। इसके साथ ही डेढ़ किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्कूलों का भी एकीकरण हो जाएगा। हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक माध्यमिक विद्यालय होगा। इस योजना से शिक्षकों की कमी की बड़ी समस्या का भी हल हो जाएगा।

शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने बताया कि योजना को बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। शिक्षा अधिकारी स्कूलों की स्थिति के आंकड़े जुटाने लग गए हैं।

चलेगा पंचायत दिवस अभियान

प्रदेश में एक जून से पंचायत दिवस अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान हर शुक्रवार को दो ग्राम पंचायतों में चलेगा। इसके तहत पंचायतों को सौंपे गए पांच विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उस ग्राम पंचायत में जाएंगे और वहां हो रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे।

अभियान के तहत मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, निर्मल राजस्थान अभियान सहित विभिन्न योजनाओं में पिछले वर्षों में हुए कामों का भौतिक सत्यापन कर नए कामों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके अलावा पंचायत कार्यालय में रिकॉर्ड रजिस्टर, कैश बुक, लेजर बुक निरीक्षण, पट्टा जारी करने, जनता जल योजना, व हैण्डपम्प मरम्मत आदि काम भी किए जाएंगे।

राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में करीब साढ़े चार माह में अभियान का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद यह लगातार चलता रहेगा।

प्रदेश में लागू हो सकती है 'श्री योजना'

गांवों के विकास के लिए प्रदेश में सरकार ने 'श्री योजना' की घोषणा की थी। इस योजना के तहत गांवों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, बिजली, सड़क व चिकित्सा सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर संभाग में संचालित किया जा रहा है। यहां प्रयोग सफल रहने के बाद पूरे प्रदेश में इसे 2 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। योजना के समन्वय का जिम्मा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को सौंपा गया है।

नहीं मिल रही फसल की सही कीमत

प्रदेश में फसल की उत्पादन लागत और केन्द्र सरकार की ओर से तय किया गए समर्थन मूल्य में काफी अन्तर है। खासतौर पर यह सरसों, गेहूं और चना जैसी कई फसलों में है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा। इससे खेती घाटे का सौदा बन गई है। कई फसलों में यह अन्तर इतना है कि राज्य सरकार की ओर से घोषित बोनस से भी पार नहीं पड़ रही।

राज्य के कृषि मंत्री का मानना है कि कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय दरें तय करता है, पर यह कम है। भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने उत्पादन लागत दरें तय की थी। प्रदेश में इस बार रिपोर्ट आने पर केन्द्र सरकार से बात की जाएगी और प्रयास करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े।

ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन

राज्य में अगले साल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। मद्देनजर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला परिषद ने सभी विकास अधिकारियों से तीन हजार की जनसंख्या वाले राजस्व गांवों की सूची मांगी है।

राज्य में वर्ष 1991 के बाद से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन नहीं हुआ है। जबकि प्रदेश के गांवों में आबादी का काफी विस्तार हो गया है। ऐसे में ग्राम पंचायतों के फिर से पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जाने लगी है। वर्ष 2011 के आधार पर तीन हजार की जनसंख्या वाले गांवों को यदि ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाता है तो कई नई पंचायतों का गठन हो सकता है।

पंचायतें नहीं हो सकी मजबूत

राज्य की पिछली सरकार के समय शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, खाद्य व नागरिक आपूर्ति तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता जैसे पांच विभाग पंचायतों को सौंप कर उन्हें मजबूत करने का दावा लगभग खोखला साबित हुआ है। सरकार ने इसके आदेश तो जारी कर दिए लेकिन हकीकत में इन विभागों की शक्तियां और बजट पंचायतों को नहीं मिल पाया।

चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में पंचायतों को सौंपे गए इन विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई है। इसमें 75 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं ने कहा है कि इन विभागों का बजट उन्हें नहीं मिला और 67 फीसदी का कहना है कि इन विभागों के सारे काम उनके जरिए नहीं हो रहे हैं।

लोकतंत्र हुआ मजबूत

राजनीतिक दलों की ओछी बयानबाजी, एक दूसरे को लांछित व अपमानित करने की होड़ और द्वेषपूर्ण अभद्र टिप्पणियों के बावजूद कुल मिला कर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। पहलीबार देश में एक चेतना की लहर दिखाई दी है। जागरूक मतदाताओं ने मजहब की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी है।

जनता ने इस बात को साबित कर दिया है कि वह लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका में हैं। इसीलिए उसने इस बार एक दल को पूर्ण बहुमत से चुना है। आमजन को नई सरकार से अपेक्षा है कि वह स्वच्छ छवि वाले सांसदों को ही मंत्रीमंडल में जगह दे साथ ही जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। - रामशरण माथुर, अलवर

अच्छा लगने लगा है

पिछले तीन दशकों के बाद देश की जनता ने एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत दिया है। भाजपा की बल्ले-बल्ले हो गई। प्रसन्नता है कि देश को मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार मिलेगी।

हालांकि मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी से निपटने के अलावा और भी अनेक चुनौतियां उनके सामने आएंगी। वह आशावादी है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार गरीबों की सोचेगी, गरीबों की सुनेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। लोगों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार होगी।

- सरिता गौड़, अजमेर

प्रदेश में बनेगा पहला बीज बैंक

दलहन, तिलहन और औषधीय पौधों की 40 हजार से भी ज्यादा विविध देशी किस्मों को संरक्षण देने के लिए प्रदेश में बीज बैंक बनाया जाएगा। इसका मकसद पौष्टिकता और गुणवत्तायुक्त देशी किस्मों की बुवाई को बढ़ावा देना और किसानों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर कृषि विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है।

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के मुताबिक इससे हमारे परंपरागत बीजों का संरक्षण होगा और किसान खुद के बीज से ही बुवाई कर सकेगा। उन्हें हर बार बाजार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महंगे हाईब्रिड बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। इससे प्रदेश के किसानों को जहां हजारों करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा, वहीं आमजन को पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

मनरेगा: 146 गांवों में रोजगार नहीं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत रोजगार देने को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत में राज्य के सभी गांवों में अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा।

सरपंच व अधिकारियों की उदासीनता के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के 18 जिलों के 146 गांवों के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। वहीं मार्च में रोजगार पाने वालों की सूची तैयार करने के लिए लगाए गए तीन दिवसीय शिविर में करीब सात लाख लोगों ने नाम दर्ज कराए हैं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485